उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा को खनन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने किया सम्मानित

ए.ए तन्हा

किच्छा। उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा को राज्य के खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों, पारदर्शिता और रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा आज दिल्ली में सम्मानित किया गया है।राजपाल लेघा कारण उनके साथ साथ उत्तराखंड का भी मान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा ने उत्तराखंड को खनन सुधारों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड की खनन नीति पारदर्शिता और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ आम आदमी के लिए बेहतर साबित हुई है। उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा को आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान (India's Honest Independence Honor) दिया गया। उनको यह सम्मान स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया। उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा को यह सम्मान उनकी निष्ठा और पारदर्शी प्रशासनिक कार्यप्रणाली के लिए 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। राजपाल लेघा को SKOCH AWARD 2025 विभाग द्वारा लागू किए गए दो प्रमुख नवाचारों-MDTSS (Mining Digital Transformation Surveillance System) और ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपरप्रको राष्ट्रीय स्तर पर SKOCH AWARD 2025 के लिए चुना गया है। उनके कार्यकाल में खनन राजस्व में अभूतपूर्व उछाल देखा गया। पिछले डेढ़ वर्षों में यह 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ तक पहुंच गया है जो लगभग चार गुना की वृद्धि है उनके इस बेहतर प्रदर्शन पर केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन (देश में दूसरा स्थान) के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि (SASCI योजना के तहत) स्वीकृत की है। खनन निदेशक राजपाल लेघा ने अपने कार्यकाल में सुधार और नवाचार (MDTSS और डिजिटलीकरण) को प्राथमिकता दी।राजपाल लेघा ने तकनीक के माध्यम से अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ई-चेक गेट और कमांड सेंटर राज्य के चार प्रमुख जिलों (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर) में 40 से अधिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं। इन पर ANPR कैमरे, RFID रडार और बुलेट कैमरे लगाए गए हैं जो 24X7 वाहनों की निगरानी करते हैं। इसके साथ ही रियल-टाइम ट्रैकिंग श्वाहन ट्रैकिंग सिस्टमश के जरिए खनिजों के परिवहन की लाइव निगरानी की जाती है, जिससे ट्रांजिट पास के उल्लंघन को रोका जा सके। श्री लेघा ने राज्य की बेहतरी के लिए पारदर्शी खनन नीति को लागू किया। उनकी खनन नीति 2023 की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा ई-रवन्ना प्रणाली डिजिटल ट्रांजिट पास और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। इन सुधारो का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव राज्य कीअर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार पर भी पड़ा है। कुमाऊं और सितारगंज स्टोन क्रेशर एसोसिएशनों ने इन सुधारों का स्वागत किया है, क्योंकि इससे बंद पड़े आधे से अधिक क्रशर फिर से शुरू हो गए हैं और इस उद्योग से लगभग 2 से 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। राजपाल लेघा को यह सम्मान उनके कर्तव्य परायणता और राज्य के हितों के लिए उनकी प्रतिबद्धता के साथ-साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में खनन क्षेत्र में किए गए बेहतर सुधारो को भी मिला है। खनन निदेशक राजपाल लेघा को मिला यह पुरस्कार इस बात को भी दर्शाता है कि आलोचना करने वाले कितनी भी आलोचना करें यदि आप अपना काम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है।

दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किए गए उत्तराखंड खनन निदेशक राजपाल लेघा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और राजपाल लेघा की जमीनी मेहनत ने खनन क्षेत्र को बुलंदियों पर पहुंचाया